THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Yes, Sir. Cost-cum feasibility survey for electrification of Kharagpur-Waltair section of which Kharagpur-Khurda Road is a portion, has been sanctioned. The survey has been entrusted to General Manager, Central Organisation for Railway Electrification, Allahabad. Survey work is presently in progress and the same is expected to be completed and report submitted by September '93.

Decreasing number of Rhinos in the Kaziranga National Park in Assam

*320. SHRI BHADRESHWAR GOHAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is gradual decrease of the Rhinos in the Kaziranga National Park in Assam;

(b) whether Government are aware that the officials are in league with the poachers in the regular killngs of Rhinos in Assam; and

(c) what steps have been taken by Government to prevent such killing and preserve these world famous species?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Rhino population in Kaziranga is reported to have declined from 1250 in 1989 to 1129 in 1991.

(b) No such report has been received from the State Government.

(c) Government continues to take measures to prevent poaching of all scheduled animals, including Rhinos, through increased patrolling of the Park and its surrounding areas, improved system of communication, building up of information network to know of poachers' activities, carrying out raids on suspected centres of trade in poached widlife products and creating a public awareness condusive to conservation of the Rhinos.

"वन क्षेत्र के विनाश को रोकने के लिये योजना"

2647. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय पौधे तथा अन्य छोटी-छोटी वनोपज देने वाले वन क्षेत्रों, जो तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं, के विनाश को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 के दौरान इस कार्य पर राज्यवार, कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) इस संबंध में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों, जो मुख्य रूप से लघु-वनोपजों और औषधीय पौधों से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या इन औषधीय पौधों तथा लघुवनोपजों के विकास हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :(क) भारत सरकार ने औषधीय पौधे और अन्य लघु वन उत्पाद की पैदावार वाले वन क्षेत्र के विनाश को रोकने के लिए तीन स्कीमें बनाई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास।

(2) अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार के कार्य में अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धन लोगों को शामिल करना।

(3) औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद वाले पौधे उगाना।

स्कीम न० (1) और (2) वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए हैं और स्कीम नं० (3) औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद उगाने के लिए है। राज्यों को विनिमुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) सहायता राज्य-वार दी जाती है और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्कीम (3) के तहत, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को लघु वन उत्पाद और औषधीय पौध उगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में निम्नलिखित वन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं:—

(1) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल।

(2) उष्णक टिबंधी वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।

(3) राष्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1989–90 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विनिर्मुक्त धनराशि

रुपये लाखों में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीम का नाम	
		जैविक हस्तक्षेप	लघु वन उत्पाद पौधे उगाना
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	14.40	17.750
2.	बिहार	—	5.00
3.	गुजरात . . .	16.325	10.00
4.	गोआ . . .	1.52	—
5.	हरियाणा . . .	22.66	—
6.	कर्नाटक . . .	54.375	—
7.	मध्य प्रदेश . . .	22.50	—

1	2	3	4
8.	मणिपुर . . .	—	11.00
9.	मेघालय . . .	6.77	27.670
10.	नागालैंड . . .	8.00	8.0
11.	उड़ीसा . . .	—	54.175
12.	पंजाब . . .	10.37	—
13.	राजस्थान . . .	—	26.250
14.	सिक्किम . . .	5.665	11.50
15.	तमिलनाडु . . .	13.2	13.50
16.	त्रिपुरा . . .	—	5.920
17.	पश्चिम बंगाल . . .	4.057	31.350
18.	दादरा और नगर हवेली . .	4.122	—
19.	अरुणाचल प्रदेश . . .	—	0.800

नोट : अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धन लोगों की भागीदारी की स्कीम वर्ष 1992-93 में ही शुरू की गई थी।

Abnormal increase of Elephant Population

2648. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that due to abnormal increase of elephant population in Assam, Arunachal Pradesh and other parts of the country, the wild elephants have become a big menace to human beings and properties;

(b) whether Government are considering to introduce 'Elephant Mahal' for catching of elephants for domestication to reduce elephant menace by amending the Wild Life (Protection) Act; and

(c) if so, the details therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) While there is no abnormal increase in the population of elephants in Assam, Arunachal Pradesh and other parts of the country, due to destruction and encroachment of elephant habitat by local people there have been confrontation between man and elephant in the fringe areas of depleted elephant habitats in some parts of the country.